दिनांक: 01.02.2025 समय:07.10PM

आकाशवाणी मध्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार

मुख्य समाचार

1- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया, 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त।
2- प्रधानमंत्री ने कहा- आम बजट एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आइना।
3- केंद्रीय बजट से मध्यप्रदेश के 72 लाख किसानों को होगा फायदा, 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिलेगा बिना गारंटी लोन।
4- आम नागरिकों से लेकर व्यपारियों और विभिन्न संगठनों ने किया आम बजट का स्वागत। बताया ऐतिहासिक।

आम बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रथम पूर्ण और अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। बजट में 1 लाख रूपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं देना होगा, इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। केन्द्रीय बजट में विकास के चार ईंजनों की पहचान की गई है, ये हैं कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इससे 1 करोड़ 70 लाख किसान लाभान्वित होंगे। यह योजना 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों में लागू किया जाएगा। संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से पांच लाख तक का लोन दिया जाएगा। एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी।

500 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्ता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व

नवाचार पहलों के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित किए गए हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया है। किराया पर टीडीएस 2.4 लाख रूपए से बढ़ाकर 6 लाख रूपए किया गया है। कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा-शुल्क-बीसीडी से छूट रहेगी। बैट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैट्री उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तू में छूट की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26, एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
श्री मोदी ने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने बजट को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि यह देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा।

शिवराज - बजट

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्रीय बजट-2025 में घोषित कपास उत्पादकता मिशन का उद्देश्य न केवल कपास की उत्पादकता बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बढ़ाना है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन के लिए फाइबर प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचे में सुधार किए जाएंगे, ताकि टिकाऊ प्राकृतिक फाइबर को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए, अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि से परिपूर्ण है।

बजट- मध्यप्रदेश

इस बजट को मध्यप्रदेश के नजरिये से देखें तो राज्य को बहुत कुछ मिला है। केंद्र सरकार ने बजट में किसान क्रेडिट कार्ड-केसीसी के ऋण की सीमा 3 लाख से

बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। इससे मध्यप्रदेश के 72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इनमें 65 लाख 83 हजार किसान और करीब साढ़े सात लाख मछली पालक है। इसी तरह पीएम स्व-निधि योजना के तहत अपना बिजनेस शुरू करने वालों के लिए अब बैंक ऋण की अधिकतम सीमा 30 हजार रुपए कर दी गई है। अब तक 10 हजार रुपए तक का ऋण मिलता था। राज्य में करीब 12 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात भी कही है । केंद्र सरकार पहले साल 10 लाख कार्ड जारी करेगी। इससे मध्यप्रदेश के 49 हजार छोटे उद्योगों को फायदा मिल सकता है। खास बात ये है कि इस बार केंद्र सरकार के बजट को तैयार करने में मध्य[प्रदेश के दो आईएएस अफसरों की भी अहम भूमिका रही है। इनमे 1991 बैच के मप्र कैडर के आईएएस मनोज गोविल और 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौड़ मुखर्जी शामिल हैं। गोविल इस समय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं दीप्ति गौड़ मुखर्जी कॉर्पोरेट अफेयर्स की सचिव हैं।

आम बजट-प्रतिक्रिया

आम बजट की घोषणाओं को लेकर प्रदेश के आम लोगों से लेकर व्यपारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी काफी उत्साहित हैं। ग्वालियर में मध्यप्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने क्या प्रतिक्रिया दी है सुनवाते हैं

उधर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आकाशवाणी से बातचीत में बजट को ऐतिहासिक बताया

दमोह के सामाजिक कार्यकर्ता धीरज जॉनसन ने भी बजट को कल्याणकारी बताया

भोपाल के व्यपारी अजय अग्रवाल बजट के बाद उत्साहित दिखे

अब कुछ समाचार संक्षेप में...

1- इंदौर पुलिस ने भोपाल के हनुमानगंज पुलिस थाने के पास स्थित गोदाम से करीब एक करोड़ रुपये की अल्प्राजोलम की गोलियों और खांसी के सिरप की बड़ी खेप बरामद कर एक थोक कारोबारी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

2- नर्मदापुरम जिले की इटारसी में इको क्लब द्वारा विश्व वेटलैंड दिवस का विशेष आयोजन किया गया। इस बार विश्व वेटलैंड्स दिवस-2025 की थीम "हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र-भूमियों की रक्षा करना" है।
3- पन्ना के जेके सीमेंट प्लांट में 30 जनवरी को हुए हादसे की जांच के लिए सागर संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने 5 सदस्यीय दल गठित किया है।
4- अनूपपुर के अमरकंटक में 3 से 5 फरवरी तक नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर

1- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया, 12 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त।
2- प्रधानमंत्री ने कहा- आम बजट एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आइना।
3- केंद्रीय बजट से मध्यप्रदेश के 72 लाख किसानों को होगा फायदा, 12 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिलेगा बिना गारंटी लोन।
और
4- आम नागरिकों से लेकर व्यपारियों और विभिन्न संगठनों ने किया आम बजट का स्वागत। बताया ऐतिहासिक।